भाजपा और उसके सहयोगियों को हराऐं जिन्होंने एसटीयू को तबाह कर दिया है, उन वाम, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को वोट दें जो आश्वासन देते हैं कि एसटीयू – एआईआरटीडब्ल्यूएफ को मजबूत और विस्तारित करना है

प्रिय भाइयों एवं बहनों,

चुनाव आयोग की ओर से जल्द ही संसदीय चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन सभी रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और उनके परिवारों से अपील करता है कि वे अपने वोट का प्रयोग भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से करें। किसी भी राजनीतिक दल को वोट देने से पहले हमें दो–तीन बार सोचना चाहिए कि हमें किसे वोट देना है। मुख्य मानदंड राज्य सड़क परिवहन निगमों की सुरक्षा और मजदूरों के हितों की रक्षा करना होना चाहिए। हमारे वोटों के सक्रिय समर्थन से केन्द्र की सत्ता पर काबिज हुई वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान एसटीयू को तबाह कर दिया है।

एमवी एक्ट संशोधन 2019 का उद्देश्य देश में मौजूदा एसटीयू को खत्म करना है। ''एग्रीगेटर्स (समूहकों) का समावेश, राज्य कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट को ट्रांसपोर्ट परमिट के रूप में एक साथ जोड़ना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के नाम पर वाहन और रूट परमिट क्लॉज से छूट देना ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो एसटीयू को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, जो पहले से ही गंभीर वित्तीय संकट की स्थितियों में हैं। न्यूनतम लाभ की गारंटी देने वाले सकल लागत अनुबंध के नाम पर निजी लोगों द्वारा संचालित फेम–2 के तहत इलेक्ट्रिकल बसों की शुरूआत एसटीयू के राजस्व को ख़त्म कर रही है।

कार्यबल में कटौती, कार्यभार में वृद्धि, रिक्तियों को न भरना, आउटसोर्सिंग के तौर पर नियुक्तियां और अन्य तरीकों से सड़क परिवहन निगमों का संकट मजदूरों पर डाला जा रहा है। कुछ एसटीयू में वेतन और सेवानिवृति हितलाभ और पेंशन का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों से पीएफ और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए वसूले जाने वाले अंशदान का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है, यह सब रोजमर्रा का रवैया बन गया है।

भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी सार्वजनिक परिवहन को सरकारी खजाने के लिए राजस्व का स्रोत नहीं माना जाता है। फरवरी 2020 में लक्जमबर्ग देश में मुफ्त परिवहन की शुरुआत की गई थी। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ शहरों में भी छात्रों जैसे यात्रियों के कुछ तबकों को मुफ्त परिवहन की सुविधा है। ब्रिटेन में छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त परिवहन सुविधा दी जाती है। दुनिया भर में सार्वजनिक परिवहन का किराया संग्रह उसके परिचालन की लागत से बहुत कम है। लेकिन दुनिया के लगभग सभी देशों में सार्वजनिक परिवहन को केन्द्र और स्थानीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। दुनिया के अनुभव के बिल्कुल विपरीत, एसटीयू में किराये की मात्रा अधिक है और उन पर केन्द्र और कई राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के करों का बोझ डाला गया है।

वादों की अवहेलनाः 2014 और 2019 के चुनावों के दौरान भाजपा और नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को 100 दिनों के भीतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करना, बेरोजगार युवाओं के लिए दो करोड़ नौकरियां पैदा करना, सभी नागरिकों के खातों में 15 लाख रुपये जमा करना आदि कुछ वादों का आश्वासन दिया। इन सभी वादों को सरकार ने सत्ता में आने के बाद झुठला दिया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, कोई नई नौकरियाँ पैदा नहीं हुई हैं बल्कि नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं। काले धन को सफेद धन बना दिया गया है। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार चरम पर हैं। एमएसपी आदि पर किसानों को दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे भी ज्यादा जनता को साम्प्रदायिक आधार पर बांटा जा रहा है।

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन सभी सड़क परिवहन निगमों के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों से अपील करता है कि वे भाजपा और सहयोगियों को हराएं और उन वामपंथी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट दें जो एसटीयू को मजबूत करने और विस्तार करने और निम्नलिखित माँगों को पूरा करके कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए आगे आते हैंः

1. आरटीसीएक्ट 1950 के अनुसार पूँजी योगदान को बहाल किया जाना चाहिए।
2. क्रूरतम एम.वी.अधिनियम संशोधन 2019 को वापस लें।
3. एसटीयू को मजबूत और विस्तारित करें।
4. आनुपातिक आधार पर एसटीयू के लिए एक बार में वृद्धि और प्रतिस्थापन दोनों के लिए नई बसों की खरीद और व्यवस्थित करें।
5. एसटीयू पर ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करें।
6. एसटीयू को लाभ और हानि के पैमाने पर नहीं मापा जाना चाहिए।
7. एसटीयू को व्यवहार्यता अंतर के फंड को बढ़ाकर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, रखरखाव और संचालन का काम सौंपा जाना चाहिए।
8. बीएनएस 2023 में दंडात्मक प्रावधान106(1)–(2) वापस लें।
9. रिक्तियों को नियमित नियुक्तियों से भरें और संविदा/आउटसोर्सिंग नियुक्तियों को वापस लें।
10. एसटीयू को पूरे देश में ईंधन स्टेशन स्थापित करने का लाइसेंस देना चाहिए।

ऑल इण्डिया रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन